

संपादकीय/समाचार

संपादकीय

न्यायिक प्रक्रिया के धीमे विकल्पों पर विचार करना होगा

उत्तमा बनाम उत्तरी दिल्ली मामले पर सुनवाई के दौरान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियों की थीं, इस मामले पर आए फैसले का अंदेशा उत्तरी हो गया था। सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए मारक प्रक्रिया बनाकर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथ जरूर बाधा देते हैं। जैसा कि हर फैसले के साथ होता है, हर पक्ष अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोधी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं इसके समर्थक इस फैसले में भी कार्रवाई के लिए राह खोज रहे हैं। इसके बाद बुलडोजर न्याय सिफी-सीडी ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेक नहीं बन पाएगा। सीडी ब्रेकर तेज रस्तावाहों की रक्खा को धीमी करता है, जबकि ब्रेक गाड़ी को रोक देता है। यह फैसला भी कृष्ण इसी तरह का सामिन होने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले एक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहां अपाराधिक मामलों की सुनवाई की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस कानून के द्वारा लगातार है, तउ अपाराध करने वालों ने अपने लिए आड़ बना रखा है। बस्तों तक धीमी गति से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का एक संदेश यह है कि ताकतवर चाहे तो अपाराध करने के बावजूद प्रक्रिया की घुमावदार गतियों में न्यायिक फैसले को टाल सकता है। यह टालना लंबा हो जाता है कि एक तरह से वह न्याय से इश्कार हो जाता है। देव है पर अधिक नहीं की सोच भी उत्तर और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के सामने धूंधली होते-होते समाप्त हो जाती है। इसी घुमावदार और लंबी-धीमी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प बनाकर बुलडोजर न्याय लगाता है। राज्य सरकारों ने इसे त्वरित न्याय के साथान के तौर पर अपाराधिक और देखते ही देखते अपाराधिक समाज की चाहत रखने वालों की चहोंती बन बैठी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की मानक प्रक्रिया बनाते हुए त्वरित न्याय के विकल्प या न्यायिक प्रक्रिया की घुमावदार गतियों को पूरी तरह नजरेंदाज किया है। यही बजह है कि इस फैसले के बाद अपाराधियों, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों के उत्तर को लेकर समाज का एक बड़ा वर्षा सर्वान्तर हो उठता है। देश की सबसे बड़ी अदालत होने वाले सुप्रीम कोर्ट को ताकतवर करने के लिए बुलडोजर न्याय और देखते ही देखते अपाराधिक समाज की चाहत रखने वालों की चहोंती बन बैठी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तरी दिल्ली के एक मामले में दिया है।

अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीर पुरी में रामनवमी के दिन निको जुलूम पर एक मर्जिन और उस इलाके से जुलूम पर हुए पथराव और उसमें उपरोक्तों के जबाब के बावजूद नार निगम ने अवैध अतिक्रमों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई को सांप्रदायिक कार्रवाई को सांप्रदायिक समाज को देखते ही देखते अपाराधिक समाज की चाहत रखने वालों की चहोंती बन बैठी है।

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रचारित सिफ़र योगी सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यही सुनवाई इसी मामले की होती रही, लेकिन संदेश ऐसा गया मानो उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इसकी वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाहनों में दिल्ली नार निगम की अवैध अतिक्रमों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी।

अब तुरंत बुलडोजर कार्रवाई नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे में स्थानीय जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जिला अधिकारी की निगरानी में होगी और इसके लिए मान्य प्रक्रिया और नोटिस आदि देने की अवैध कानूनी तरह निवेदण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की राह में एक बाध नजर आ रही है। जिला प्रशासन समय और काम के बोझ का बहाना बनाकर ऐसी कार्रवाई को टाल सकता है। अपराधी, माफिया और गैंगस्टर कब्जे करते हो रहे हैं। इसके लिए गैंगस्टर और राजनीतिक चबूत्रों के बीच संदेश यही गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आया फैसला है।

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रचारित सिफ़र योगी सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आंशिक तेजानां, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि सरकारों ने भी की है। एक आंकड़े के सुधारक फिल्में सात सालों में कीरीब 2000 अवैध अतिक्रमण बुलडोजर कार्रवाई में छापा हुआ है।

जिनमें सबसे ज्यादा कीरीब डेढ़ हजार मामले उत्तर प्रदेश की ही रहे।

लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई से खाली कीरीब 14 नवंबर से भिवानी से की है।

कर्नल सोमवीर डबास और फर्स्ट एफिसर राजेश कुमार की जीत रही है।

अब तुरंत बुलडोजर कार्रवाई नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं का विषय रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे में स्थानीय जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जिला अधिकारी की निगरानी में होगी और इसके लिए मान्य प्रक्रिया और नोटिस आदि देने की अवैध कानूनी तरह निवेदण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की राह में एक बाध नजर आ रही है। जिला प्रशासन समय और काम के बोझ का बहाना बनाकर ऐसी कार्रवाई को टाल सकता है। अपराधी, माफिया और गैंगस्टर कब्जे करते हो रहे हैं। इसके लिए गैंगस्टर और राजनीतिक चबूत्रों के बीच संदेश यही गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आया फैसला है।

इसे में न्याय की उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में न्याय की उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

वाहन चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराधिक तत्वों पर लगाम लगा पाना आसान नहीं रह जाएगा।

गिरफ्तारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद

समाचार गेट/सुमित गोयल

फरीदाबाद। अपराध शाखा बरपुर बॉर्डर की टीम ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गस्त के दौरान मोटरसाइकिल सहित बाइ-पारोड सेक्टर 37 से गिरफ्तार किया है। जिसका मामला थाना सपर खाली में 12 सिंतंबर को दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी रही उम्मीद भी धूंधली होगी। ऐसे में अपाराध

एक और बाघ की मौत, संकट में आजाएगा मध्यप्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा

-बाघ की भौत ने वन विभाग को लापरवाही उजागर की थी। भौताल। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत ने दर्जीजीव प्रेसिडेंसी और वन विभाग को हिल रखा दिया है। दशकों में प्राप्त हुई यह बाघ की मृत अवस्था में प्राप्त हुई। दशकों में एक बाघ की मृता पोर्टर्टार्टमेंट से चलता। रिपोर्ट के अनुसार, बाघ को चोट लगाने के कारण शिकायत करने में असमर्थ हो गया था, और वह कई दिनों तक इधर-उत्तर भटकता रहा। बाघ ने जंगल में भौत जीवी की तालिश की, लेकिन अतंत-भौत जीवी में खाली पर अपनी जीवी खो दी। यह घटना विशेष रूप से वित्त का विषय थी, यद्यपि बाघ का शब्द एक रिहायी डलाके के नजदीक मिला था, और आसापास के ग्रामीणों ने बाघ के मूर्मेट की सूखाना दी थी। इसके बावजूद, वन विभाग ने समय रहते थाने नहीं दिया। विभाग द्वारा जंगल में पेट्रोटिंग और सीसीटीवी नियंत्रण की जा रही है, फिर भी बाघ बाघ का पाता नहीं चल पाया। जहां एक और मध्यप्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पेंच टाइगर रिजर्व में मई 2024 के पांच बाघों का शव मिला, जीवों तक जाली माले में करते लगाने वाले कारोंण से बाघों की मौत सामने आई है। 2023 में भी करते लगाने वाले एक बाघ का शिकायत करने की घटना सामने आई थी।

बहराइच में तेंदुए के हमले में चार वर्षीय बालक की मौत, गांव में कोहराम

बहराइच। बहराइच जिले के बाजपुर गांव में तेंदुए के हमले में एक बाघ वर्षीय बालक की दुखद मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बहुरुद्ध संदर्भ में हुई है, जिसमें एक बालक ने दोस्तों के बीच खेतों पर अपनी पत्ती और बालों के बीच खेतों में काम कर रहे थे, जबकि उनका बैटा अभिनन्दन खेल रहा था। अन्यानक, खेत में डिप्टी तेंदुए ने बच्चे पर छापा कर बच्चे को अपार मुंह में दबोचकर सरयु नहर की ओर भाग गया। इस बाद गम्भीर रूप से घायल बच्चे को परिजन तुरत प्राथमिक रुपास्थ के बाद ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वन विभागीय अधिकारी अश्विन गोडे ने घटना की जानकारी देकर कहा कि पीड़ित परिवार को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

पाकिस्तान से बांगलादेश पहुंचे 300 से ज्यादा कंटेनर, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने बांगलादेश को समृद्ध के रस्ते ही याताहार के अनुसार, यह घटना बहुरुद्ध संदर्भ में एक बालक ने दोस्तों के बीच खेतों के बीच खेतों में खेतों में गया था। तभी संदीप और उनकी बाली खेतों में काम कर रहे थे, जबकि उनका बैटा अभिनन्दन खेल रहा था। अन्यानक, खेत में डिप्टी तेंदुए ने बच्चे पर छापा कर बच्चे को अपार मुंह में दबोचकर सरयु नहर की ओर भाग गया। इसके बाद गम्भीर रूप से घायल बच्चे को परिजन तुरत प्राथमिक रुपास्थ के बाद ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वन विभागीय अधिकारी अश्विन गोडे ने घटना की जानकारी देकर कहा कि पीड़ित परिवार को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

20 नवंबर को मतदान के कारण 6 राज्यों में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी

नई दिल्ली। 20 नवंबर को बारांगांड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, करेल और उत्तराखण्ड में मतदान होना है जिसके चलते यहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह राज्यों में स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोर्ट और एसी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ताकि मतदान दिन किसी बाधा के अपेक्षा मतदान का डर्स्टमाल कर सकें। बारांगांड में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है यहां दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 12 जिलों के 528 उम्मीदवार में होने वाले 1.23 करोड़ से ज्यादा मतदान आपेक्षित किया गया है। करोड़ 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुपाव होना है। जिसमें फलूपार, गाजियाबाद, मध्यावा, खेंर, मीरापुर, सीसामुक्त, कढ़ीरी, करहल और कुदरकों सीटें हैं। जाली में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 4,140 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा हैं। वाही यहीं पर 9 विधान

